

[2023] 5 एस. सी. आर. 712

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

ए.

भारतबेन चंद्रकांतभाई ठाकुर बनाम.

गुजरात राज्य और अन्य (2013 की सिविल अपील संख्या 24) 27 फरवरी, 2023

बी.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई, पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

सेवा कानून:त्यागपत्र-पेंशन बकाया-अपीलार्थी, सहायक नर्स मिडवाइफ ने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया, हालांकि, इसकी स्वीकृति से पहले इसे वापस ले लिया-इसके बाद, उन्हें अपनी सेवा फिर से शुरू करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई-इसके बहुत बाद उनका त्यागपत्र स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया गया-उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि अपीलार्थी सभी परिणामी लाभों का हकदार था-हालांकि, खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को इस हद तक संशोधित किया कि अपीलार्थी को उस अवधि के लिए किसी भी लाभ का हकदार नहीं माना गया था जिसके लिए त्यागपत्र लागू था-अपील पर कहा गया:"जिस अवधि के लिए त्यागपत्र लागू था" की अभिव्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने के बाद की तारीख तक नहीं बढ़ाया जा सकता था, इससे पहले कि यह लागू हो-इस्तीफे की अवधि पर विवाद और जिस तरीके से त्यागपत्र को माना जाना था, वह अंतिम हो जाने के बाद राज्य के लिए इस प्रकृति का क्रमिक आदेश पारित करना जारी रखना खुला नहीं था-अपीलार्थी केवल अपना त्यागपत्र जमा करने की तारीख से लेकर अपना त्यागपत्र वापस लेने की तारीख के बीच की अवधि के लिए किसी भी परिणामी लाभ का हकदार नहीं था-अपीलार्थी ने 24 साल 10 महीने और 5 दिन की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है, इस प्रकार, 25 साल की न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है-अपीलार्थी को देय पेंशन देय राशि की गणना उस आधार पर की जानी चाहिए, चाहे कोई भी आदेश पारित किया गया हो।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

सिविल अपील न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.24

2013.

2007 के एल. पी. ए. No.70 और 2006 के एस. सी. ए. No.14636 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.02.2009 के निर्णय और आदेश से।

एच.

712

713

भारतबेन चंद्रकांतभाई ठाकुर बनाम गुजरात राज्य ए.

ए.

नचिकेता जोशी, सुश्री हिमाद्री हक्सर, अजय शुक्ला, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायालय के निर्णय द्वारा दिया गया था

बी.

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. अपीलार्थी को 15 जनवरी 1980 को जिला पंचायत, वलसाड द्वारा सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में नियुक्त किया गया था।उन्होंने 18 अप्रैल 1993 को सेवा से अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन 23 नवंबर 1993 को इसे वापस ले लिया।20 दिसंबर 1993 को उन्हें सेवा फिर से शुरू करने के लिए बुलाया गया था।हालाँकि उन्हें 16 अप्रैल 1994 तक शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी।दिसंबर 1994 को 31 मार्च 1993 से उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया गया था।इसने अपीलार्थी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका 1 की स्थापना को जन्म दिया।

सी.

डी.

2. 12 अक्टूबर 2000 के एक फैसले द्वारा, गुजरात उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने दिसंबर 1994 के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि अपीलार्थी सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

3. गुजरात राज्य द्वारा दायर एक लेटर्स पेटेंट अपील 2 में, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने पाया कि अपीलार्थी को बिना उसकी गलती के अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की

अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि, खंड पीठ ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता उस अवधि के लिए किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा जिसके लिए इस्तीफा लागू था।

ई.

4. उपरोक्त कथन इंगित करता है कि अपीलार्थी के इस्तीफे से संबंधित मुद्दे ने 22 फरवरी 2001 के डिवीजन बेंच के फैसले के साथ अंतिमता प्राप्त की। जाहिर है, अपीलार्थी ने अपना इस्तीफा स्वीकार करने से पहले ही वापस ले लिया था। दिसंबर 1994 में 31 मार्च 1993 से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के सरकार के आदेश का कानून में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उच्च न्यायालय के निर्णय का परिणाम यह था कि 23 नवंबर 1993 को वापस लिए गए अपीलार्थी के सेवा से इस्तीफे का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। डिवीजन बेंच के फैसले का एकमात्र परिणाम यह था कि एकल न्यायाधीश ने

एफ.

जी.

1 1995 की विशेष सिविल अपील संख्या 10418 2 2001 की पेटेंट अपील संख्या 97

एच.

714

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि अपीलार्थी सभी परिणामी लाभों की हकदार होगी, डिवीजन बेंच ने कहा कि वह उस अवधि के लिए लाभों की हकदार नहीं होगी जिसके लिए इस्तीफा लागू था। दूसरे शब्दों में, यह अवधि 18 अप्रैल 1993 से 23 नवंबर 1993 तक होगी।

5. उपरोक्त कानूनी स्थिति के बावजूद, प्रत्यर्थी द्वारा शुरू में 8 अप्रैल 2002 को एक आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि (i) 24 नवंबर 1993 से 30 मार्च 2001 तक की अवधि को अनधिकृत अवकाश माना जाएगा; और (ii) उपरोक्त अवधि को बिना वेतन के सेवा में विराम माना जाएगा। इसके बाद 17 जुलाई 2002 को इस्तीफे की अवधि को अनधिकृत अवकाश मानते हुए इसी तरह का आदेश पारित किया गया।

बी.

6. 8 अप्रैल 2002 और 17 जुलाई 2002 के दो आदेशों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नई कार्यवाही की स्थापना की। 9 अगस्त 2004 के एक फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने 8 अप्रैल 2002 और 17 जुलाई 2002 के उपरोक्त दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। प्रत्यर्थीगणों को 24 नवंबर 1993 से 30 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए 22

फरवरी 2001 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ सभी लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। राशि का भुगतान 2004 में किया गया था और ब्याज तत्व का भुगतान 2012 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त 2004 के उच्च न्यायालय के फैसले को अंतिम रूप दिया गया। फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी।

सी.

डी.

7. 16 जुलाई 2005 को, प्रत्यर्पणों द्वारा एक तीसरा आदेश पारित किया गया था जिसमें निम्नलिखित अवधि को अनधिकृत अवकाश के रूप में रखा गया था और इसे सेवा में विराम के रूप में माना जाना था, अर्थात्;

ई.

(i) 21 जून 1988-31 जुलाई 1988-41 दिन; (ii) 18 अप्रैल 1993-23 नवंबर 1993-220 दिन; और (iii) 6 नवंबर 1991-7 अप्रैल 1993-521 दिन।

एफ.

8. उपरोक्त आदेश ने अपीलार्थी के कहने पर अनुच्छेद 226 के तहत तीसरी याचिका 4 को जन्म दिया। 25 जुलाई 2006 के अपने विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि 782 दिनों की अवधि में सेवा से उनकी अनुपस्थिति के कारण सेवा की कोई निरंतरता नहीं दी जा सकती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। एकल न्यायाधीश के 25 जुलाई 2006 के फैसले की 17 फरवरी 2009 को डिवीजन बेंच द्वारा अपील में पुष्टि की गई है। इसलिए मामला इस अदालत में चला गया है।

जी.

3 2002 का विशेष सिविल आवेदन सं. 9723 4 2006 ए का विशेष सिविल आवेदन सं. 14336

एच.

715

भारतबेन चंद्रकांत ठाकरे बनाम गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

9. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता श्री नचिकेता जोशी और गुजरात राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता सुश्री स्वाति घिल्लियाल को सुना है। 10. अपीलार्थी ने 18 अप्रैल 1993 को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन 23 नवंबर 1993 को इसे वापस ले लिया। इस्तीफे को स्वीकार करने का आदेश बहुत बाद में दिसंबर 1994 को पारित किया गया था। इस आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। जबकि एकल न्यायाधीश ने सभी परिणामी लाभों के अनुदान का निर्देश दिया था, डिवीजन बेंच ने एक लेटर्स पेटेंट अपील में फैसले को

इस हद तक संशोधित किया कि अपीलार्थी को उस अवधि के लिए किसी भी लाभ का हकदार नहीं माना गया था जिसके लिए इस्तीफा लागू था। इसलिए, लेटर्स पेटेंट अपील में डिवीजन बेंच के फैसले के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी 18 अप्रैल 1993 और 20 दिसंबर 1993 के बीच किसी भी परिणामी लाभ का हकदार नहीं था। 11. "जिस अवधि के लिए इस्तीफा लागू था" अभिव्यक्ति को 23 नवंबर 1993 को इस्तीफा वापस लेने के बाद की तारीख तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

बी.

सी.

12. उपरोक्त स्थिति के बावजूद, इसके बाद 8 अप्रैल 2002 और 17 जुलाई 2002 को दो आदेश पारित किए गए। दोनों आदेशों को 9 अगस्त 2004 को उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, जिसमें प्रत्यर्थागणों को नवंबर 1993 और मार्च 2001 के बीच ब्याज के साथ परिणामी लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

डी.

13. अपीलार्थी द्वारा दूसरी रिट याचिका में सफल होने के बाद भी, 16 जुलाई 2005 को एक और आदेश पारित किया गया। 16 जुलाई 2005 के तीसरे आदेश में जिन तीन अवधियों का उल्लेख किया गया है, उनमें से यह स्पष्ट है कि 41 दिनों की पहली अवधि जून 1988 और जुलाई 1988 के बीच है जो सेवा से इस्तीफे की तारीख से पहले की है। अप्रैल और नवंबर 1993 के बीच 220 दिनों की दूसरी अवधि त्यागपत्र जमा करने के बाद और इसे वापस लेने तक की अवधि है जो पहले से ही 22 फरवरी 2001 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का विषय बन गया था। हालाँकि 521 दिनों की अंतिम अवधि 6 नवंबर 1991 और 7 अप्रैल 1993 के बीच है। यह अवधि 16 जुलाई 2005 को पारित आदेश में निर्धारित की गई है। स्पष्ट रूप से, इस्तीफे की अवधि पर विवाद और इस्तीफे को जिस तरीके से निपटाया जाना था, वह अंतिम रूप प्राप्त करने के बाद राज्य के लिए इस तरह के क्रमिक आदेश पारित करना जारी रखने के लिए खुला नहीं था। अपीलार्थी केवल 18 अप्रैल 1993 से 23 नवंबर 1993 के बीच की अवधि के लिए किसी भी परिणामी लाभ का हकदार नहीं था।

ई.

एफ.

जी.

14. अपीलार्थी को 30 नवंबर 2011 को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है। पिछले 11 वर्षों से, अपीलार्थी ने

एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

केवल अस्थायी पेंशन दी गई। जिस आदेश द्वारा अपीलार्थी को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है, वह इंगित करता है कि अपीलार्थी ने 31 वर्ष की कुल सेवा में से 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन पेंशन योग्य सेवा पूरी की है।

15. जिन कारणों से हमने इस निर्णय के पाठ में संकेत दिया है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी को 25 साल की न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाला माना जाना चाहिए। अपीलार्थी को देय पेंशन देय राशि की गणना राज्य सरकार द्वारा पारित किसी भी आदेश की परवाह किए बिना उस आधार पर की जाएगी। पेंशन भुगतान जिसकी अपीलार्थी इस आधार पर हकदार है कि उसने 25 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है, इस आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर गणना की जाएगी। अपीलार्थी को उस तारीख से देय पेंशन के बकाया का भुगतान किया जाएगा जिस तारीख को उसकी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की गई थी, उसके बाद एक महीने की अवधि के भीतर अपीलार्थी को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा।

बी.

सी.

डी.

16. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी गई है और 17 फरवरी 2009 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को खारिज कर दिया गया है।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

ई.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: राखी, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.